

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निदेशक अनुश्रवण,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:- 16/09/26

विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजना- BR43 Development of Infrastructure Facilities for Judiciary(9174) अंतर्गत परियोजनाओं की विवरणी न्याय विकास पोर्टल पर अपलोड किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7514, दिनांक-11.09.2026 एवं विभागीय पत्रांक-7083(भ)अनु., दिनांक-29.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विधि विभाग से संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजना- BR43 Development of Infrastructure Facilities for Judiciary (9174) अंतर्गत न्याय विकास पोर्टल पर परियोजनाओं की विवरणी अपलोड/अद्यतन किये जाने हेतु दिनांक-20.09.2026 तक नई समय सीमा निर्धारित की गयी है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी प्रासंगिक विभागीय पत्र के द्वारा दिनांक-31.07.2026 तक योजनाओं की विवरणी न्याय विकास पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु पूर्ण रूप से सभी योजनाओं की विवरणी अपलोड नहीं किया गया था।

अतः अनुरोध है कि उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत सभी शेष चालू परियोजनाओं की विवरणी न्याय विकास पोर्टल पर अचूक रूप से दिनांक-20.09.2026 तक अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

बासनो शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

संवा में,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांक.....

विषय:-

न्याय विकास पोर्टल पर छूटे हुये चालू प्रोजेक्ट्स को अपलोड करने के संबंध में।

प्रसंग:-

अवर सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं०-J-11017/04/2021-JR-Part(1)(E-8427), दिनांक-09.09.2026

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि न्याय विकास पोर्टल पर छूटे हुये चालू प्रोजेक्ट्स को अपलोड करने की समय-सीमा दिनांक-09.09.2026 से 20.09.2026 तक निर्धारित की गई है। यह उन चालू परियोजनाओं को अपलोड करने का अंतिम अवसर है, जो दिनांक-31.03.2026 से पूर्व स्वीकृत हो चुकी है परन्तु तकनीकी कारणों से पोर्टल पर अपलोड होने से छूट गई थी।

अतः अनुरोध है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त निदेश के आलोक में संबंधित सभी छूटी हुई चालू परियोजनाओं को दिनांक-20.09.2026 तक अपलोड कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे। क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसके बाद समय-सीमा में कोई विस्तार नहीं किया जायेगा।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(बासनो शंकर मेहरोत्रा)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक 7514/जे० पटना, दिनांक 11.9.26

प्रतिलिपि:- निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-3702-1
11-9-26

(बासनो शंकर मेहरोत्रा)

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

11/9/26

3539
11/9/26
2196/50000
14/9

जी एन प्रमोद जी
14/9/26

15-9-26

No. J-11017/03/2021-JR-Part (1) (E-8427)

Government of India
Ministry of Law & Justice
Department of Justice

Jaisalmer House,
26, Man Singh Road, New Delhi - 110011
Dated: 9th September, 2026

Law/Home Secretary/PWD Secretary
All State Governments/UTs

Subject: Extension of timeline for "Add New Project" Tab on Nyaya Vikas Portal — reg.
of Madam.

I am directed to refer to this Department's earlier communication regarding the enabling of the "Add New Project" tab on the Nyaya Vikas Portal for uploading ongoing projects sanctioned prior to 31.03.2026 and with some expenditure also done) which were inadvertently left out from the Portal.

In this regard, it has now been decided to provide a final extension for uploading such left-out ongoing projects. Accordingly, the "Add New Project" tab on the Nyaya Vikas Portal has been enabled with effect from 09.09.2026 and will remain enabled till 20.09.2026.

States/UTs are requested to upload only those ongoing projects inadvertently left out from uploading on the Portal by 20.09.2026. This may be treated as the final extension, and no further extension will be considered thereafter.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Kiran Gopal Dhakate)
Under Secretary to Govt. of India
Email: jr-infra.doj@gov.in
Tel. No.: 011-23072140

Copy to:

1. Registrar General of the concerned High Courts for information and necessary action.